Q.1) निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है?

1. न्यायपालिका के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति
2. व्ययों का भारत के समेकित कोष पर भारित होना
3. न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है
4. न्यायाधीशों के आचरण पर केवल संसद में चर्चा हो सकती है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 4
c) 1,2 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.1) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	असत्य	असत्य
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति (जिसका अर्थ कैबिनेट की सलाह पर) द्वारा न्यायपालिका के सदस्यों (यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों) के परामर्श से किया जाता है। यह प्रावधान कार्यपालिका के पूर्ण विवेकाधिकार पर अंकुश लगाता है तथा साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक नियुक्तियां किसी भी राजनीतिक या व्यावहारिक प्रक्रियाओं पर आधारित नहीं हैं।	न्यायाधीशों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के सभी प्रशासनिक खर्चों को भारत के समेकित कोष पर भारित किया गया है। इस प्रकार, वे संसद द्वारा गैर-मतदान योग्य हैं (हालांकि उन पर चर्चा की जा सकती है)।	सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को आवधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद से केवल उस तरीके से और संविधान में वर्णित आधारों पर हटाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर नहीं रहते हैं, हालांकि वे उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अब तक नहीं हटाया गया है (या महाभियोग लगाया गया है)।	संविधान संसद में या राज्य विधानमंडल में किसी भी चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में उनके कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है, सिवाय जब महाभियोग प्रस्ताव संसद में विचाराधीन हो।

Q.2) सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. किसी भी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय दे सकता है या अपनी राय देने से इंकार कर सकता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सलाहकारी होती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.2) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
संविधान (अनुच्छेद 143) राष्ट्रपति को मामलों की दो श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है: a. कानून या सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर जो उत्पन्न हुआ है या जो उत्पन्न होने की संभावना है। b. किसी भी संविधान-पूर्व संधि, समझौते, वाचा, अंत:क्रिया, या अन्य समान साधनों से उत्पन्न विवाद पर। पहले मामले में, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है या राय देने से मना कर सकता है। लेकिन, दूसरे मामले में, सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को 'अवश्य' अपनी राय देनी होगी। दोनों मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सलाहकारी होती है तथा न्यायिक घोषणा नहीं होती है।	

Q.3) अभिलेख-न्यायालय (Court of Record) के रूप में, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई हैं?

1. सर्वोच्च न्यायालय के अभिलिखित किए गए निर्णयों पर प्रश्न नहीं किया जा सकता है, जब किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.3) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
अभिलेख न्यायालय (Court of Record) के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय के पास दो शक्तियाँ हैं: a. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और कार्य सदा स्मृति और साक्ष्य के लिए दर्ज किए जाते हैं। इन अभिलेखों को स्पष्ट मूल्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है तथा किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर पूछताछ नहीं की जा सकती है। वे कानूनी मिसाल और कानूनी संदर्भ के रूप में पहचाने जाते हैं। b. इसमें न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है, यह या तो छह महीने तक के लिए साधारण कारावास या 2,000 तक जुर्माना या दोनों के साथ होती है। 1991 में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि उसके पास न केवल स्वयं की बल्कि पूरे देश में उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ अदालतों और न्यायाधिकरणों की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है।	

Q.4) राष्ट्रीय आपातकाल (National emergency) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. आपातकाल की घोषणा दोनों सदनों से अनुमोदन के बिना 6 महीने से अधिक बनी रह सकती है।
2. इसे संसदीय स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
3. इसे भारत में 1975 के बाद केवल एक बार घोषित किया गया है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3

d) उपरोक्त सभी

Q.4) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसकी घोषणा की तारीख से एक महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में जारी की जाती है, जब लोकसभा भंग कर दी गई हो या लोकसभा का विघटन एक महीने की अवधि के दौरान उद्घोषणा को मंजूरी दिए बिना हो जाता है, तो उद्घोषणा, लोकसभा के पुनर्गठन के बाद, पहली बैठक से 30 दिनों तक बनी रहती है (इसमें 6 महीने लग सकते हैं), बशर्ते राज्यसभा ने इस बीच इसे मंजूरी दे दी हो।	राष्ट्रपति द्वारा बाद में किसी भी समय आपातकाल की घोषणा रद्द की जा सकती है। इस तरह की उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।	1975 के पश्चात् कोई भी आपातकाल लागु नहीं हुआ है, कारगिल युद्ध के दौरान भी नहीं।

Q.5) राष्ट्रीय आपातकाल (National emergency) के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

1. राज्य सरकारें निलंबित हो सकती हैं, जब आपातकालीन स्थिति संचलन में हो।
2. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून, आपातकाल की समाप्ति के बाद भी परिचालन में रहते हैं।
3. आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति संसद की मंजूरी के बिना केंद्र से राज्यों को वित्त हस्तांतरण को रद्द कर सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.5) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	असत्य
एक राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को उस तरीके के बारे में निर्देश देने के लिए विस्तारित होती है, जिस तरीके से उसकी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग	राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के छह महीने बाद निष्क्रिय हो जाते हैं।	जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा चल रही हो, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका अर्थ है कि

किया जाना है। सामान्य समय में, केंद्र केवल कुछ निर्दिष्ट मामलों पर किसी राज्य को कार्यकारी निर्देश दे सकता है। हालाँकि, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, केंद्र किसी भी 'मामले' पर किसी राज्य को कार्यकारी निर्देश देने का हकदार बन जाता है। इस प्रकार, राज्य सरकारों को केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में लाया जाता है, हालांकि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है।		राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को वित्त हस्तांतरण को कम कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। इस तरह का संशोधन वित्तीय वर्ष के अंत तक जारी रहता है जिसमें आपातकाल संचालित होता है। साथ ही, राष्ट्रपति के ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए।

Q.6) मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत छह मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं।
2. अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी लागू रहते हैं।
3. आपातकाल के दौरान ली गई विधायी और कार्यकारी कार्रवाइयों को आपातकाल के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) केवल 2
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.6) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	**सत्य**	**असत्य**
अनुच्छेद 358 के अनुसार, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत छह मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। उनके निलंबन के लिए कोई अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, 1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 के दायरे को प्रतिबंधित कर दिया। अनुच्छेद 19 के तहत छह मौलिक अधिकार केवल तभी निलंबित किए जा सकते हैं, जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाए, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।	44 वें संशोधन अधिनियम के बाद, अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 20) तथा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21) आपातकाल के दौरान भी लागू रहने योग्य होता है।	44 वें संशोधन के अनुसार, केवल संबंधित कानून के तहत आपातकाल के दौरान की गई कार्यकारी कार्रवाई संरक्षित है तथा विधायी कार्रवाई संरक्षित नहीं है।

Q.7) राष्ट्रपति शासन (President's rule) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जा सकता है, जब कोई राज्य केंद्र से निर्देश का पालन करने में विफल रहता है।
2. राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।
3. संसद राष्ट्रपति शासन लगने के दौरान, राज्य बजट पारित करती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.7) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
अनुच्छेद 365 कहता है कि जब भी कोई राज्य केंद्र के किसी भी दिशा-निर्देश का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि जिसमें राज्य में शासन संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य कर सके। ।	राष्ट्रपति शासन की घोषणा या उसकी निरंतरता को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल एक साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, अर्थात उस सदन के उपस्थित सदस्य और मतदान करने वालों का बहुमत हो।	राष्ट्रपति या तो राज्य विधान सभा को निलंबित या भंग करता है। संसद राज्य विधायी बिल और राज्य बजट पारित करती है।

Q.8) राष्ट्रपति शासन के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान, राज्य कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाता है तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित या भंग कर दी जाती है।
2. राष्ट्रपति शासन के निरसन के लिए लोकसभा को प्रस्ताव पारित करना होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.8) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
इसके संचालन के दौरान, राज्य की कार्यकारिणी बर्खास्त कर दी जाती है तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित या भंग कर दी जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का संचालन करता है और संसद राज्य के लिए कानून बनाती है।	ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसे राष्ट्रपति द्वारा केवल अपनी स्वयं की शक्तियों के आधार पर निरस्त किया जा सकता है।

Q.9) वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसे अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रत्येक वर्ष संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
2. इसके संचालन के दौरान, केंद्र राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.9) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है। इसका तात्पर्य दो चीजों से है: 1. इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है; तथा 2. इसके जारी रहने के लिए बार-बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।	वित्तीय आपातकाल के संचालन के दौरान, केंद्र वित्तीय मामलों में राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करता है।

Q.10) बोम्मई मामले (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया, जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ हैं?

1. त्रिशंकु विधानसभा (Hung assembly)
2. कुशासन (Maladministration)
3. केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों की अवहेलना
4. कठोर वित्तीय अनिवार्यता (Stringent financial exigencies)

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 3
b) 2 और 3
c) 1,3 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.10) Solution (a)

कथन 1	कथन 3	कथन 2	कथन 4
सत्य	सत्य	असत्य	असत्य
एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रभाव निम्नलिखित स्थितियों में उचित होगा: 1. जहां विधानसभा के आम चुनावों के बाद, कोई		एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुचित होगा: 1. जहां एक सरकार इस्तीफा देती है या	

भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं करती है, यानी 'त्रिशंकु विधान सभा'। 2. जहाँ विधानसभा में बहुमत रखने वाली पार्टी सरकार गठन से इंकार कर देती तथा राज्यपाल को कोई गठबंधन सरकार गठन के लिए विधानसभा में बहुमत की शक्ति वाला नहीं मिल रहा है। 3. जहां एक सरकार विधानसभा में अपनी पराजय के बाद इस्तीफा दे देती है तथा कोई अन्य पार्टी विधानसभा में बहुमत रखने वाली सरकार के गठन लिए तैयार या सक्षम नहीं होती है। 4. जहां केंद्र सरकार के एक संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है। 5. आंतरिक उपद्रव जहां, उदाहरण के लिए, एक सरकार जानबूझकर संविधान और कानून के खिलाफ काम कर रही है या एक हिंसक विद्रोह कर रही है। 6. भौतिक विखंडन, जहां सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने से इनकार कर राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है।	विधानसभा में बहुमत का समर्थन खोने पर बर्खास्त कर दी जाती है तथा राज्यपाल वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना देखे बिना राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। 2. जहां राज्यपाल स्वयं विधानसभा में एक सरकार के समर्थन का अपना आकलन करता है तथा उन्हें विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित करने की अनुमति दिए बिना राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। 3. जहां विधानसभा में बहुमत का समर्थन करने वाली सत्ताधारी पार्टी को 1977 और 1980 की तरह लोकसभा के आम चुनावों में भारी हार का सामना करना पड़ा हो। 4. आंतरिक गड़बड़ी आंतरिक उपद्रव या भौतिक विखंडन की सीमा तक नहीं हो। 5. राज्य में कुप्रबंधन या सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप या राज्य की कठोर वित्तीय अनिवार्यता। 6. जहां राज्य सरकार को विनाशकारी परिणाम के लिए अत्यधिक आग्रह के मामले को छोड़कर स्वयं को सुधारने के लिए पूर्व चेतावनी नहीं दी जाती है। 7. जहां सत्ता का उपयोग सत्ता पक्ष की अंतर-पार्टी समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है, या एक उद्देश्य के लिए जो बहिष्कृत या अप्रासंगिक है, जिसके लिए इसे संविधान में उल्लेख किया गया है।

Q.11) सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निर्णय करने का मूल, अनन्य और अंतिम अधिकार है।
2. संघ सूची में मामलों के संबंध में इसके अधिकार क्षेत्र और शक्तियां संसद द्वारा विस्तारित की जा सकती हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.11) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में विवादों	सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और संघ सूची में

का निर्णय करता है। इस संबंध में, इसके पास मूल, अनन्य और अंतिम प्राधिकार है।	मामलों के संबंध में शक्तियां संसद द्वारा विस्तारित की जा सकती हैं। इसके अलावा, इसके अधिकार क्षेत्र और अन्य मामलों के संबंध में शक्तियों को केंद्र और राज्यों के एक विशेष समझौते द्वारा विस्तारित किया जा सकता है।

Q.12) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यूएसए के सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ किसी भी मामले में अपील करने के लिए विशेष अवकाश (special leave) देने का व्यापक विवेकाधिकार है।
2. यूएसए के विपरीत, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा का दायरा अधिक व्यापक है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.12) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	**असत्य**
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण (सैन्य को छोड़कर) के फैसले के खिलाफ किसी भी मामले में अपील करने के लिए विशेष अवकाश (special leave) प्रदान करने का एक बहुत विस्तृत विवेकाधिकार है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसी कोई पूर्ण शक्ति नहीं है।	भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत विस्तृत है।

Q.13) भारतीय संविधान के अनुसार, न्यायिक समीक्षा का दायरा कहाँ तक सीमित है

1. मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
2. कानून, उस प्राधिकरण की सक्षमता से बाहर है, जिसने उसे बनाया है
3. तर्कशीलता, उपयुक्तता या नीतिगत निहितार्थ का प्रश्न

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.13) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3

सत्य	सत्य	असत्य
विधायी अधिनियम या कार्यकारी आदेश की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में निम्नलिखित तीन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। a. यह मौलिक अधिकारों (भाग III) का उल्लंघन करता है, b. यह उस प्राधिकरण की सक्षमता से बाहर है, जिसने इसे बनाया है, और c. यह संवैधानिक प्रावधानों के लिए प्रतिकूल है। हमारा सर्वोच्च न्यायालय, किसी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय, केवल ठोस प्रश्न की जाँच करता है, अर्थात् कानून संबंधित प्राधिकारी की शक्तियों के भीतर है या नहीं। इसकी तर्कशीलता, उपयुक्तता या नीतिगत निहितार्थ के प्रश्न पर जाने की आशा नहीं है।		

Q.14) सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित याचिकाएं पीआईएल के रूप में स्वीकार की जा सकती हैं?

1. महिलाओं पर अत्याचार के विरुद्ध याचिकाएँ
2. पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित याचिकाएँ
3. उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए याचिकाएँ

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.14) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
1998 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पीआईएल के रूप में प्राप्त पत्रों या याचिकाओं को देखने के लिए दिशानिर्देशों का एक समूह तैयार किया। इन दिशा-निर्देशों को 1993 और 2003 में संशोधित किया गया था। उनके अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले पत्रों या याचिकाओं को आमतौर पर जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाएगा: 1. बंधुआ श्रमिक मामले 2. उपेक्षित बच्चे 3. श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना तथा सामयिक श्रमिकों का शोषण और श्रम कानूनों के उल्लंघन की शिकायतें (व्यक्तिगत मामलों को छोड़कर) 4. जेलों से याचिकाएं जैसे उत्पीड़न की शिकायत, पूर्व-परिपक्व रिहाई के लिए और जेल में 14 साल पूरे होने के बाद रिहाई की मांग, जेल में मौत, स्थानांतरण, व्यक्तिगत बांड पर रिहाई, मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई 5. मामला दर्ज करने से इंकार करने पर पुलिस के खिलाफ याचिका, पुलिस द्वारा उत्पीड़न और पुलिस हिरासत में मौत		निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले मामलों को पीआईएल के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा: 1. मकान मालिक-किरायेदार मामले 2. सेवा मामला तथा जो पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित हैं 3. (1 से 10 तक) पिछले बिंदुओं से संबंधित लोगों को छोड़कर केंद्र / राज्य सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें। 4. चिकित्सा और अन्य शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश 5. उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की

6. महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ याचिकाएँ, विशेष रूप से दुल्हन, दुल्हन को जलाने, बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि। 7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों से सह-ग्रामीणों या पुलिस द्वारा ग्रामीणों के उत्पीड़न या यातना की शिकायत करने वाली याचिकाएं 8. पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक संतुलन की गड़बड़ी, ड्रग्स, खाद्य अपमिश्रण, विरासत और संस्कृति के रखरखाव से संबंधित याचिकाएँ, प्राचीन वस्तुएँ, वन और वन्य जीवन और सार्वजनिक महत्व के अन्य मामले 9. दंगा-पीड़ितों से याचिकाएँ 10. पारिवारिक पेंशन	जल्द सुनवाई के लिए याचिकाएँ

Q.15) भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संसद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित कर सकती है।
2. संसद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से समाप्त कर सकती है।
3. संसद समय-समय पर उच्च न्यायालय की सदस्य संख्या (strength) का निर्धारण करती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.15) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
संसद एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विस्तारित कर सकती है या किसी केंद्र प्रशासित क्षेत्र से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर कर सकती है।		संविधान एक उच्च न्यायालय के सदस्य संख्या को निर्दिष्ट नहीं करता है तथा इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ देता है। तदनुसार, राष्ट्रपति इसके कार्यभार के आधार पर समय-समय पर उच्च न्यायालय में सदस्य संख्या का निर्धारण करता है।

Q.16) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सी योग्यता संविधान में निर्धारित है?

1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए।
3. उसे दस वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.16) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य

एक व्यक्ति को एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए, उसके पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. (a) उसे दस वर्षों के लिए भारत के क्षेत्र में एक न्यायिक पद रखना चाहिए; या
   (b) उन्हें दस वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए।

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के मामले के विपरीत, संविधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रतिष्ठित न्यायविद की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं करता है।

Q.17) भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
2. वित्तीय आपातकाल के दौरान, न्यायाधीशों के वेतन को उनकी नियुक्ति के बाद कम किया जा सकता है।
3. न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, राज्य के समेकित निधि पर भारित होते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.17) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
न्यायपालिका के सदस्यों (यानी, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) के परामर्श से एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति (जिसका अर्थ कैबिनेट की सलाह) द्वारा की जाती है। यह प्रावधान कार्यपालिका के पूर्ण विवेक पर अंकुश लगाता है तथा साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक नियुक्तियां किसी भी राजनीतिक या व्यावहारिक प्रक्रियाओं पर आधारित नहीं हैं।	एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, छुट्टी और पेंशन समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन, वित्तीय आपातकाल के आलावा उनकी नियुक्ति के बाद उनके लाभ शर्तों में कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें उनके पद के कार्यकाल के दौरान समान बनी रहती हैं।	न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्रशासनिक खर्चों को राज्य के समेकित निधि पर भारित किया जाता है। इस प्रकार, वे राज्य विधायिका (हालांकि इस पर चर्चा की जा सकती हैं) द्वारा गैर-मतदान योग्य होते हैं। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत के समेकित कोष पर भारित होती है, न

		कि राज्य पर।

Q.18) निम्नलिखित में से किस मामले में, उच्च न्यायालय भारत में मूल क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) का आनंद लेते हैं?

1. संसद के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद
2. नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन
3. शादी और तलाक के मामले

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.18) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य

मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है उच्च न्यायालय में प्रथम दृष्टया विवादों को सुनने की शक्ति, अपील के माध्यम से नहीं। यह निम्नलिखित तक विस्तृत है:

a. वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानूनों और अदालत की अवमानना के मामले।
b. संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद।
c. राजस्व मामले के बारे में या राजस्व संग्रह में आदेशित या किया गया अधिनियम।
d. नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन।
e. मामलों को एक अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया जिसमें संविधान की व्याख्या इसकी फाइल में शामिल थी।
f. चार उच्च न्यायालयों (यानी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालयों) में उच्च मूल्य के मामलों (cases of higher value) में मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र हैं।

Q.19) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तहत स्थापित कानूनी सेवा प्राधिकरणों के प्राथमिक कार्य हैं

1. पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना
2. लोक अदालतों का आयोजन करना
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित करना

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.19) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तहत स्थापित कानूनी सेवा प्राधिकरण नियमित आधार पर निम्नलिखित मुख्य कार्यों का निर्वहन करते हैं:

1. पात्र व्यक्तियों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना।
2. विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित करना।

Q.20) लोक अदालतों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

a) लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं।
b) लोक अदालत के पास वैसी ही शक्तियां हैं, जैसी कि एक सिविल कोर्ट में निहित होती हैं।
c) लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में निहित होती है।
d) उपरोक्त सभी सही हैं।

Q.20) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
लोक अदालत के निर्णय को दीवानी न्यायालय का आदेश या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जाएगा। लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा और विवाद के सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।	लोक अदालत में उतनी ही शक्तियां हैं जितनी कि सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) के तहत एक सिविल कोर्ट में निहित हैं।	लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ कोई अपील किसी न्यायलय में नहीं होगी।

Q.21) वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (NSFI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रणनीति का लक्ष्य सभी टियर- II से टियर VI केंद्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विभिन्न तरीकों के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।
2. इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है।
3. सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री का 2022 तक पुर्णतः परिचालन रणनीति के उद्देश्यों में से एक है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है / हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 2 और 3
d) केवल 1 और 3

Q.21) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य
रणनीति का लक्ष्य सभी टियर- II से टियर VI केंद्रों में डिजिटल वित्तीय	वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (NSFI) भारतीय रिज़र्व बैंक	NSFI में कुछ अन्य उद्देश्य: प्रत्येक वयस्क की मार्च 2024 तक

सेवाओं के विभिन्न तरीकों के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है तथा मार्च 2022 तक कम नकदी वाले समाज की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करना है।	(RBI) द्वारा 2019-2024 की अवधि के लिए जारी की गई है।	मोबाइल डिवाइस के माध्यम से वित्तीय सेवा प्रदाता तक पहुंच बनानी है; हर इच्छुक और योग्य वयस्क, जिसे पीएम जन धन योजना के तहत नामांकित किया गया है, को मार्च 2020 तक बीमा योजना और पेंशन योजना के तहत; मार्च 2022 तक सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री को पूरी तरह से चालू करने के लिए नामांकित किया जा सकता है।

Q.22) 'एक ट्रिलियन वृक्ष पहल' (One Trillion Trees Initiative), हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा आरंभ किया गया था?

a) खाद्य और कृषि संगठन (FAO)
b) संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCCD)
c) प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN)
d) विश्व आर्थिक मंच (WEF)

Q.22) Solution (d)

- एक ट्रिलियन वृक्ष पहल (One Trillion Trees Initiative) को **विश्व आर्थिक मंच** ने 2020 की बैठक में 2030 तक विश्व भर में 1 ट्रिलियन पेड़ों को उगाने, पुनर्स्थापित करने और संरक्षित करने के लिए लॉन्च किया है।
- इसका उद्देश्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, व्यवसायों और व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर प्राकृतिक बहाली में एकजुट करना है।
- वैश्विक पहल जैव विविधता को बहाल करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के उद्देश्य से है।

Q.23) भारत ने निम्नलिखित में से किसके साथ प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते (Migration and Mobility Partnership Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं?

a) रूस
b) फ्रांस
c) जापान
d) कनाडा

Q.23) Solution (b)

- भारत और फ्रांस के मध्य लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता, भारत और फ्रांस के बीच छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों की गतिशीलता को बढ़ावा देता है।
- यह दोनों पक्षों के बीच अनियमित प्रवासन और मानव तस्करी से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने में भी मदद करेगा।

Q.24) ट्रूनेट टेस्ट (TrueNat Test) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह तपेदिक निदान के लिए एक स्वदेशी आणविक नैदानिक उपकरण है।

2. यह एक पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (polymerase chain reaction -PCR) आधारित परीक्षण है, जो चिप् के उपयोग से दवा प्रतिरोध का भी पता लगा सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.24) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
ट्रूनेट टेस्ट (TrueNat Test) तपेदिक निदान के लिए एक स्वदेशी आणविक नैदानिक उपकरण है। यह गोवा स्थित मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स द्वारा विकसित किया गया था, जिसे डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में समर्थन किया था।	ट्रूनेट एक पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (पीसीआर) आधारित परीक्षण है, जो टीबी बैक्टीरिया में मौजूद जीन को परखकर, न केवल बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगा सकता है, बल्कि चिप् के उपयोग के साथ दवा प्रतिरोध का भी पता लगा सकता है। ट्रूनेट टेस्ट आसानी से और लागत प्रभावी रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सेटअप किया जा सकता है।

Q.25) निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

बौद्ध मठ स्थल	राज्य
1. मोघलमारी	उत्तर प्रदेश
2. बोज्जनकोंडा	आंध्र प्रदेश
3. लिंगलामेत्ता	कर्नाटक

ऊपर दी गई कौन सी जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है?

a) केवल 1 और 3
b) केवल 1
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.25) Solution (a)

- मोघलमारी पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के प्रारंभिक मध्यकाल का एक बौद्ध मठ स्थल है।
- बोज्जनकोंडा और लिंगलामेत्ता मठ: ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के शंकरम गाँव में जुड़वां शिलाकृत बौद्ध मठ हैं। वे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की हैं।

Q.26) 'मिशन इनोवेशन' (Mission Innovation) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए 24 देशों और यूरोपीय संघ की एक वैश्विक पहल है।
2. यह 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (CoP 21) के दौरान लॉन्च किया गया था।

सही कथनों का चयन करें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.26) Solution (c)

30 नवंबर, 2015 को भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अग्रणी प्रयासों के कारण मिशन इनोवेशन की घोषणा की गई थी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के महत्वाकांक्षी प्रयासों के लिए विश्व नेता पेरिस में एक साथ आए थे। मिशन इनोवेशन (एमआई) 24 देशों और यूरोपीय संघ की एक वैश्विक पहल है, जो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में नाटकीय रूप से तेजी लाने के लिए है। परिवर्तनकारी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निजी क्षेत्र के निवेश के अधिक से अधिक स्तर को प्रोत्साहित करते हुए, पहल के एक भाग के रूप में, भाग लेने वाले देशों ने अपनी सरकारों के स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और विकास (R&D) निवेशों को दोगुना करने के लिए पांच साल में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध किया है।

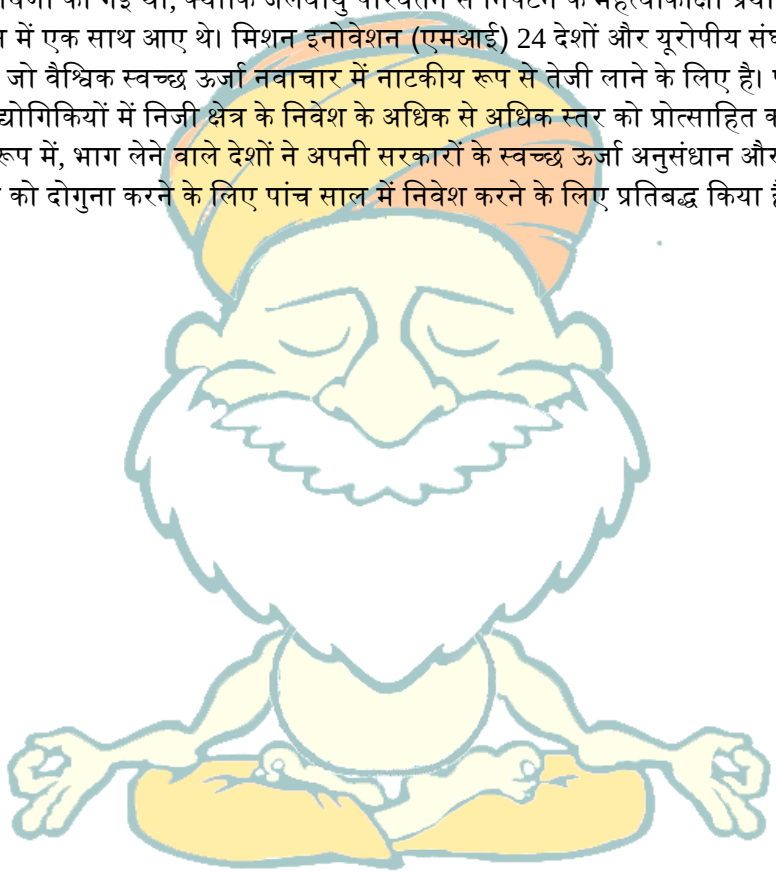

Q.27) 'भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक' किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है

a) विश्व आर्थिक मंच
b) विश्व बैंक
c) ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

d) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

Q.27) Solution (c)

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 1995 के बाद से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाने वाला एक सूचकांक है, जो "सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के उनके कथित स्तरों द्वारा विशेषज्ञ मूल्यांकन और राय सर्वेक्षणों द्वारा निर्धारित देशों को रैंक करता है।"

Q.28) 'जूस जैकिंग' (Juice Jacking) के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है।

a) यह एक प्रक्रिया है, जिसमें क्रिप्टोक्यूरेंसी के विभिन्न रूपों के लिए लेनदेन को सत्यापित किया जाता है तथा ब्लॉकचेन डिजिटल लेज़र में जोड़ा जाता है।
b) यह एक प्रकार का साइबर-हमला है जिसमें एक चार्जिंग पोर्ट शामिल होता है, जैसे आमतौर पर USB, जिस पर डेटा कनेक्शन को दोगुना कर देता है।
c) यह किसी ऐसे व्यक्ति का दिखावा करने की क्रिया है जैसे आप ऑनलाइन नहीं हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को लुभाने के लिए जिससे आप कभी किसी संबंध में नहीं रहे।
d) यह एक इलेक्ट्रॉनिक संचार में भरोसेमंद इकाई के रूप में अपने आप को छिपाने के द्वारा उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का धोखाधड़ी का प्रयास है।

Q.28) Solution (b)

यह एक प्रकार का साइबर-हमला है जिसमें एक चार्जिंग पोर्ट शामिल होता है, जैसे आमतौर पर USB, जिस पर डेटा कनेक्शन को दोगुना कर देता है। इसमें अक्सर स्मार्ट फोन, टैबलेट, या अन्य कंप्यूटर डिवाइस से संवेदनशील डेटा की प्रतिलिपि बनाने वाले मैलवेयर इंस्टॉल करना शामिल होता है।

Q.29) 'एन चंद्रशेखरन समिति' का गठन किस कार्य को देखने के किया गया था

a) कृत्रिम बुद्धिमत्ता
b) 3 डी प्रिंटिग
c) बिग डाटा
d) एल्गोरिथम ट्रेडिंग (Algorithm Trading)

Q.29) Solution (a)

एन चंद्रशेखरन समिति: सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग और अनुप्रयोग का अध्ययन करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति।

Q.30) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. लिथियम-सल्फर (Li-s) बैटरी लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी की तुलना में काफी अधिक ऊर्जा स्टोर करती है।
2. लिथियम-सल्फर (Li-s) बैटरी को आमतौर पर उत्पादन की कम लागत, ऊर्जा दक्षता और बेहतर सुरक्षा के कारण लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी की उत्तराधिकारी माना जाता है।

सही कथनों का चयन करें

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.30) Solution (c)

सैद्धांतिक रूप से, लिथियम-सल्फर बैटरी लिथियम-आयन की तुलना में पांच गुना अधिक ऊर्जा रखने में सक्षम होती हैं।

लिथियम-सल्फर बैटरी को आमतौर पर उत्पादन की कम लागत, ऊर्जा दक्षता और बेहतर सुरक्षा के कारण लिथियम-आयन (ली-आयन) बैटरी की उत्तराधिकारी माना जाता है। उनके उत्पादन की लागत कम होती है क्योंकि सल्फर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

लिथियम आयन बैटरी को अपने सकारात्मक इलेक्ट्रोड का उत्पादन करने के लिए दुर्लभ पृथ्वी तत्व, निकल और कोबाल्ट जैसे खनिजों की आवश्यकता होती है। इन धातुओं की आपूर्ति सीमित है, कीमतें बढ़ रही हैं, तथा उनके खनन में अक्सर महान सामाजिक और पर्यावरणीय लागत होती है।